

माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

स्रोत: PIB

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया, जो भारत की GST यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह न्यायाधिकरण विवादों के समाधान को सुगम बनाने और भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) क्या है?

- **परिचय:** जीएसटीएटी (GSTAT) एक वैधानिक निकाय है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करना है।
 - यह करदाताओं को विशिष्ट और स्वतंत्र मंच प्रदान करेगा, जिससे GST प्रणाली में व्यवस्था, पूर्वानुमेयता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- **उद्देश्य:** जीएसटीएटी का लक्ष्य पूरे भारत में जीएसटी विवादों के लिए एक एकीकृत अपीलीय मंच तैयार करना है ("वन नेशन, वन फोरम")। यह जीएसटी कानूनों में कानूनी टकराव और अस्पष्टता को कम करता है।
 - इसका उद्देश्य विवादों का समयबद्ध समाधान करना है, ताकि नकदी प्रवाह और व्यापारिक निश्चिंता में सुधार हो।
 - जीएसटीएटी साधारण भाषा में नरिणय, सरल प्रारूप, चैकलसिट और वरचुअल सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करता है। यह 'नागरिक देवो भव' और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के सिद्धांतों के अनुरूप नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है।
- **कार्यप्रणालियाँ:**
 - जीएसटीएटी का संचालन नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ (Principal Bench) और देशभर में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों (State Benches) के माध्यम से किया जाता है, जिससे इसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच सुनिश्चित होती है।
 - प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक सदस्य, 1 केंद्रीय तकनीकी सदस्य और 1 राज्य तकनीकी सदस्य होते हैं, ताकि न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञता के समन्वय से नष्पिकष और सुसंगत नरिणय दिये जा सकें।
 - इसे तीन 'S' के आधार पर तैयार किया गया है:
 - **Structure (संरचना):** न्यायिक + तकनीकी विशेषज्ञता
 - **Scale (वसितार):** राज्य पीठों और सरल मामलों के लिये एकल सदस्यीय पीठें
 - **Synergy (समन्वय):** प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएँ और मानवीय विशेषज्ञता
 - जीएसटीएटी ई-कोर्ट पोर्टल करदाताओं और प्रैक्टिशिनरों के लिये ऑनलाइन दाखला, मामले की ट्रैकिंग और वरचुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है।
- **लाभ:**
 - बड़े और छोटे दोनों प्रकार के करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है तथा न्याय में अनावश्यक देरी नहीं होने देता।
 - अस्पष्टता को कम तथा पूरे भारत में व्याख्या में समानता और सुसंगतता सुनिश्चित करता है।
 - नविशकों का विश्वास बढ़ाता है और एमएसएमई, नरियातकों, स्टार्टअप्स तथा नागरिकों के लिये कर अनुपालन को सरल बनाता है।
 - डिजिटल पोर्टल करदाताओं को ऑनलाइन अपील दाखल करने, मामलों को ट्रैक करने और वरचुअल सुनवाई में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।

और पढ़ें...: अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ GST 2.0

UPSC सविलि सेवा परीक्षा के पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????

प्रश्न. नमिन्लखिति मदों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपरयुक्त मदों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतरगत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज़ टैक्स/GST)' के क्रयान्वति कयि जाने का/के सर्वाधकि संभावति लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधकिरणों द्वारा वसूल कयि जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापति करेगा ।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदिशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सक्षम बनाएगा ।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे नकिट भवषिय में चीन से आगे नकिलने में सक्षम बनाएगा ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)